www.vidarbhakibaat.in

Post Reg. No. RNP/NPCITY /169 /2015-2017

प्रखर... मुखर... स्वर

विदर्भ की बात

● वर्ष 17 ● अंक 135 नागपुर, मंगलवार, 11 अप्रैल 2017 ● पृष्ठ 8 ● मूल्य ₹ 2

सुप्रभात

जम्मू-कश्मीर: कुपवाड़ा में 4 आतंकी ढेर, सेना का सर्च ऑपरेशन जारी

श्रीनगर

सेना ने उत्तरी कश्मीर में एलओसी के साथ सटे केरन (कुपवाडा) सेक्टर में बीती रात सरहद पार से घुसपैठ के एक प्रयास को नाकाम बनाते हुए चार आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों के अन्य साथियों को जिंदा अथवा मुर्दा पकड़ने के लिए सेना क जवानों ने पूरे इलाके में तलाशी अभियान जारी रखा हुआ है।

रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि रविवार देर रात घुसपैठ की गयी थी। मारे गए आतंकियों की तत्काल पहचान नहीं हो पाई है। हालांकि मारे गए आतंकियों के साथ एक या दो आतंकी और थे जो वापस गुलाम कश्मीर भाग गए हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर मुठभेडस्थल के आस पास के इलाके को खंगाला जा रहा है ताकि अगर कोई आतंकी जिंदा है और वहीं कहीं छिपा है तो उसे भी मार गिराया जा सके।

आपको बता दें कि पिछले हफ्ते भी पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कई कोशिशें हुई जिसे सेना ने नाकाम कर दिया। सीजफायर उल्लंघन कर पाकिस्तान घुसपैठियों को कश्मीर में भेजता रहा है। पिछले हफ्ते पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तान ने संघर्षविराम का उल्लंघन करते हुए लगातार दो दिनों गोलीबारी की थी।

कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह पर कस सकता है शिकंजा

नई दिल्ली

कॉमनवेल्थ गेम्स में हुए भ्रष्टाचार के मामलों में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर भी शिकंजा कड़ा होता दिखाई दे रहा है। इसकी वजह पब्लिक अकाउंट कमेटी का उस विवादित रिपोर्ट को स्वीकार करना है जिसमें मनमोहन सिंह पर कई तरह के आरोप लगाए गए थे। इसमें उनके प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए सुरेश कलमाड़ी को इन गेम्स के आयोजन वाली कमेटी का अध्यक्ष चुनने और इस दौरान हुए भ्रष्टाचार पर सवाल खड़े किए गए थे। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक पीएसी ने 14 जनवरी 2005 को तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रियों की बैठक और इसमें दिए गए खेल मंत्रालय के बयानों को भी सिरे से खारिज कर दिया है।

इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जब तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह के पास इस प्रोजेक्ट को लेकर बात आई थी तो उन्होंने इसकी जिम्मेदारी दूसरे को देने की बजाए पहले से निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक इसको आगे बढ़ाने का निर्णय लिया था। इसके अलावा इसकी रिपोर्ट बनाने में भी करीब दो माह की देरी की गई। अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक राजनीतिक दबाव की वजह से इस दौरान केबिनेट सचिवालय इस बाबत जिम्मेदारी तय करने में भी नाकाम रहा। वहीं यूपीए 2 के दौरान इस पर विचार किया गया। भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में बनी पीएसी ने इस बाबत सामने आई कैग की रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया जिसमें कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजन में अनियमितता बरतने की बात कही गई थी।

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच छह समझौतों पर हुए हस्ताक्षर

नई दिल्ली

चार दिवसीय भारत यात्रा पर रविवार को आए आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल ने पीएम मोदी के साथ मिलकर दोनों देशों के रिश्तों को एक नए आयाम पर लेकर जाने की बात कही है। सोमवार को दोनों देशों के बीच छह समझौतों पर मुहर लगी है, जिनमें सबसे अहम है आतंकवाद के खात्मे के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध समेत छह महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं। पीएम मोदी और उनके समकक्षीय टर्नबुल के बीच अपसी हितों को लेकर द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों की व्यापक चर्चा हुई।

जल्द होगी अगले दौर की व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता वार्ता

टर्नबुल के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्होंने दोनों देश के रिश्तों की समीक्षा की है उसे आगे ले जाने की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं, जिसमें जल्द होनेवाली अगले दौर की व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता वार्ता शामिल है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थायित्व पर जोर देते हुए मोदी ने कहा कि आतंकवाद और साइबर सुरक्षा से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर रणनीति और उसके समाधान की जरूरत है।

आतंकवाद के खिलाफ समन्वय बढ़ाने पर समझौता

दोनों देशों के बीच आतंकवाद निरोधक समन्वय को बढ़ाने के लिए गृह मंत्रालय और उनके समकक्षीय ऑस्ट्रेलियन मंत्रालय के बीच समक्षौते पर हस्ताक्षर किए गए। एक तरफ जहां पीएम मोदी ने कहा ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम की भारत को आपूर्ति करने के लिए पूरी तरह से तैयार था तो वहीं टर्नबुल ने कहा कि उसकी सरकार जल्द से जल्द यूरेनियम भारत को सप्लाई करने का प्रयास करेगी। ■ शेष पृष्ठ 2 पर

दिल्ली मेट्रो में मोदी और आस्ट्रेलियाई पीएम टर्नबुल ने की यात्रा

नई दिल्ली की यात्रा पर आए आस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल ने सोमवार को दिल्ली मेट्रो की सवारी की।

इस दौरान उनके साथ भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी भी रहे। ये यात्रा दिल्ली के मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन से शुरु होकर अक्षरधाम तक पूरी हुई।

दोनों नेताओं ने अपनी यात्रा के दौरान सेल्फी भी खींची

विकास का प्रतीक बन चुकी दिल्ली मेट्रो की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा होती है। दोनों नेता जब मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन पहुंचे तो स्थानीय अधिकारी ने मेट्रो नेटवर्क और इसके विस्तार को लेकर जानकारी दी।

इस दौरान आस्ट्रलियाई पीएम काफी उत्सुक दिखाई दे। अक्षरधाम मंदिर में उतरने के बाद पीएम मोदी ने आस्ट्रलियाई पीएम को भारत के सांस्कृतिक विरासत की जानकारी दी।

फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ की थी मेट्रो यात्रा

इससे पहले भी पीएम नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ दिल्ली मेट्रो में यात्रा कर चुके हैं। 25 अप्रैल 2015 को धौला कुआं से द्वारका के बीच उन्होंने ये यात्रा की थी। साथ ही बदरपुर–फरीदाबाद मेट्रो लाइन के उद्घाटन पर 6 सितंबर 2015 को मेट्रो में यात्रा की थी। ये दौर यही नहीं थमा था, 25 जनवरी, 2016 को पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ दिल्ली से गुड़गांव की यात्रा मेट्रो ट्रेन से की थी।

2008 की ऋण छूट से कुछ ही किसानों को मिला फायदा - फडणवीस

मुंबई

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2008 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने किसानों के कर्ज को माफ कर दिया था, लेकिन कृषि ऋण छूट का फायदा केवल 30 से 40 फीसदी किसानों को मिला था, बल्कि सही मायनों में जिन किसानों की स्थिति अधिक खराब थी, उन किसानों तक इसका लाभ नहीं पहुंचा।

उन्होंने कहा कि ऋण माफी अंतिम उपाय नहीं है, लेकिन कई में से एक है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कैग रिपोर्ट में बताया गया है कि कर्जमाफी का लाभ केवल 30-40 प्रतिशत किसानों को हुआ था।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने रविवार को आधे घंटे का खुद के शीर्षक मी मुख्यमंत्री बोलतोय नामक टीवी शो लॉन्च किया। फडणवीस ने कहा पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम से प्रेरणा लेते हुए महीने में एक बार इस शो के जरिए जनता से बात करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं इस विचार का नहीं हूं कि किसानों का कर्ज कभी माफ नहीं चाहिए। मेरा मानना है कि कर्जमाफी उचित समय पर की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया कि लोग सोशल मीडिया, ईमेल के माध्यम से अपने प्रश्न भेजेंगे और कार्यक्रम के दौरान कुछ ही व्यक्ति उपस्थित होंगे।

भारत ने कहा, कुलभूषण जाधव की फांसी पाक की सुनियोजित रणनीति का हिस्सा

नई दिल्ली

भारतीय नौसेना के पूर्व अफसर कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान मिलिट्री की तरफ से सुनाई गई मौत की सज़ा ने एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से जारी रिश्तों की कड़वाहट को और बढ़ाने का काम किया है। सोमवार को मिलिट्री ट्रिब्यूनल की तरफ से जाधव को फांसी की सज़ा सुनाए जाने की रिपोर्ट्स सामने आने के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित को समन भेजकर इस बारे में जवाब तलब किया।

भारत के तेवर तल्ख

विदेश सचिव एस. जयशंकर ने कहा कि जाधव को खिलाफ जो प्रक्रिया अपनायी गई, जिसके चलते उन्हें फांसी दी गई वह हास्यास्पद है। उन्होंने कहा, बिना किसी पुख्ता सबूत के जो प्रक्रिया अपनाकर उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई है वह हास्यास्पद है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे उच्चायोग को यह भी नहीं बताया गया कि जाधव को ट्रायल को लिए लाया जा रहा था।

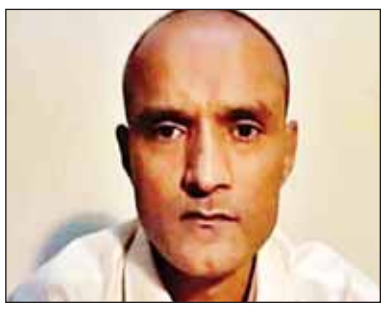

एस. जयशंकर ने डिमार्शे (डिप्लोमैटिक डिमांड लेटर) जारी करते हुए कड़े शब्दों में कहा कि अगर इस मामले में न्याय और कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है तो भारत और यहां के लोग जाधव की फांसी को सुनियोजित हत्या मानेंगे।

इससे पहले, पाकिस्तान आर्मी की तरफ से एक बयान जारी कर यह बताया गया कि मिलिट्री ट्रिब्यूनल ने बलूचिस्तान से मार्च 2016 में गिरफ्तार किए गए कुलभूषण जाधव को जासूसी और देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाया। सेनाध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से हस्ताक्षरित आदेश में पूर्व भारतीय नेवी ऑफिसर को मौत की सज़ा दी गई है।

भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान में मौत की सजा सुनाई गयी है। आइएसपीआर ने एक ट्वीट के जरिए बताया है कि कुलभूषण को जासूसी करने के आरोप में यह सज़ा सुनाई गयी है। कुलभूषण पर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का एजेंट होने का आरोप लगा था। कुलभूषण जाधव को मार्च 2016 में बलूचिस्तान से जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, कुलभूषण जाधव के जासूसी के इस आरोप को भारत सिरे से नकारता रहा है। इससे पहले, दिसंबर 2016 में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा था कि जाधव के पास से बरामद डोजियर में कुछ खास नहीं है और न ही जाधव के खिलाफ कोई सबूत मिला। उसके बाद कुलभूषण जाधव को लेकर एक उम्मीद जगी थी। लेकिन, उसके बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर से साफ किया कि कुलभूषण जाधव पाकिस्तान में भारत के लिए जासूसी कर रहा था जिसका उसके पास पर्याप्त सबूत है। ■ शेष पृष्ठ 2 पर

बिहार की राह पर मध्यप्रदेश

प्रदेश में लागू होगी शराबबंदी- सीएम शिवराज

भोपाल

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से शराब की सभी दुकानें बंद कर प्रदेश में शराबबंदी लागू की जाएगी। ये बात उन्होंने प्रदेश में चल रही नर्मदा सेवा यात्रा के 113वें दिन नरसिंहपुर जिले के ग्राम नीमखेड़ा में जनसंवाद कार्यक्रम में रविवार शाम को कही।

उन्होंने कहा, प्रथम चरण में नर्मदा नदी के दोनों तटों पर पांच-पांच किलोमीटर तक शराब की

दुकानें एक अप्रैल से बंद कर दी गई हैं। अगले चरण में अब रिहायशी इलाकों, शिक्षण संस्थाओं और धार्मिक स्थलों के पास शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। चौहान ने जोर देकर कहा कि मध्यप्रदेश में नशामुक्ति का आंदोलन चलेगा। गौरतलब है कि पिछले एक माह में प्रदेश के विभिन्न इलाकों में शराब की दुकानों के विरोध में लोगों द्वारा प्रदर्शन किए गए हैं।

रायसेन जिले के बरेली कस्बे में पांच अप्रैल को प्रदर्शनकारियों ने रिहायशी इलाके में शराब की दुकान खोलने का विरोध करते हुए आबकारी विभाग और शराब ठेकेदार के दल के दो वाहनों में आग लगा दी थी। साथ ही चार वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया था।

कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले में पांच आरोपियों को मिली जमानत

नई दिल्ली

उद्योगपति नवीन जिंदल से जुड़े कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले के मामले में सीबीआइ द्वारा बनाए गए अतिरिक्त पांच आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। सीबीआइ द्वारा दाखिल की गई अंतिम जांच रिपोर्ट में पांच नए आरोपी बनाए गए थे। रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने सभी आरोपियों को पेश होने का निर्देश दिया था। विशेष सीबीआइ जज भरत पराशर ने नवीन जिंदल के सलाहकार आनन्द गोयल, गुरुग्राम की कंपनी ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के उपाध्यक्ष सिद्धार्थ मदरा, निहार स्टॉक लिमिटेड के निदेशक एसबीएन सूर्यनारायण, मुंबई की कंपनी केई इंटरनेशनल के सीएफओ राजीव अग्रवाल और मुंबई की ही एसआर पावर लिमिटेड के उपाध्यक्ष सुशील कुमार मारो को एक लाख के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के जमानती पर अंतरिम जमानत प्रदान कर दी।

मुझे इस बात का दुःख है कि सिंध आज भारत का हिस्सा नहीं - आडवाणी

नई दिल्ली

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने नई दिल्ली में आयोजित इंडिया फाउंडेशन के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, आज सिंध भारत में नहीं है इससे मुझे दुख होता है। भारत का वह हिस्सा जहां मेरा जन्म हुआ, भारत की आजादी के बाद अलग हो गया। उन्होंने कहा, किसी देश का नाम नहीं लेना चाहूंगा पर एशिया में भी कई देश हैं जिनके साथ संबंध सहज हो जाएं तो मुझे खुशी होगी। आपको बता दें कि बटवारे से पहले आडवाणी का जन्म कराची में एक सिंधी परिवार में हुआ था। बचपन की यादें जुड़ीं होने कारण आडवाणी कई बार सार्वजनिक तौर पर स्वीकार चुके हैं कि कराची उनका पसंदीदा शहर है। इसी साल जनवरी में प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था, कभी-कभी मैं महसूस करता हूं कि कराची और सिंध अब भारत का हिस्सा नहीं रहे। ■ शेष पृष्ठ 2 पर

ईवीएम विवाद पर अब सर्वदलीय बैठक बुलाएगा चुनाव आयोग

नई दिल्ली

ईवीएम की विश्वसनीयता पर उठे सियासी सवालों को तूल पकड़ता देख चुनाव आयोग ने अब इस पर सर्वदलीय बैठक बुलाने का फैसला किया है। आयोग ने 16 विपक्षी दलों की ईवीएम की खामियों को दूर करने या फिर आगे के चुनावों को बैलेट पेपर के जरिए ही कराने की मांग के मद्देनजर यह बैठक बुलाने का निर्णय लिया है।

कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी पार्टियों ने सोमवार को चुनाव आयोग से मुलाकात कर बैलेट पेपर की पुरानी प्रणाली पर लौटने की मांग की थी। विपक्षी दलों ने ईवीएम विवाद पर एकजुट होकर काम करने की रणनीति बनाई है। इसी रणनीति के तहत विपक्षी दलों ने चुनाव

आयोग में शिकायत की तो बुधवार को राष्ट्रपति से ईवीएम मुद्दे पर मिलने का समय मांगा है।

राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद की अगुवाई में 16 पार्टियों के प्रतिनिधिमंडल की चुनाव आयोग से हुई मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि उनकी शिकायतों पर आयोग ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर चर्चा करने की बात कही है।

उनका कहना था कि सभी पार्टियों की बैठक में ईवीएम की विश्वसनीयता पर उठे सवालों पर चर्चा की जाएगी। विपक्षी दलों ने आयोग को ज्ञापन सौंप कहा कि हाल के चुनावों में ईवीएम को लेकर लोगों का भरोसा टूट गया है क्योंकि बटन दबाने पर एक पार्टी विशेष के पक्ष में ही वोट गिरने की घटनाएं सामने आयी हैं।

इसलिए चुनाव में लोगों का भरोसा कायम रखने के लिए आयोग ईवीएम की खामियों को दूर करने और पेपर ट्रेल मशीन की व्यवस्था होने तक चुनाव बैलेट पेपर से ही कराए जाने चाहिए। विपक्षी पार्टियों ने गुजरात और हिमाचल प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव को बैलेट पेपर से कराने का भी आयोग को सुझाव दिया है।

चुनाव आयोग से मुलाकात करने से पूर्व संसद भवन में सुबह गुलाम नबी आजाद की अगुवाई में इन सभी विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक हुई। इसमें कांग्रेस के कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा के साथ ईवीएम विवाद को सबसे पहले तूल देने वाली बसपा के सतीश मिश्र, तृणमूल कांग्रेस के सुखेंदु शेखर राय, सपा के नीरज शेखर, जदयू के अनवर अली के अलावा माकपा, भाकपा, द्रमुक, एनसीपी, राजद आदि के भी नेताओं ने शिरकत की।

इसी बैठक में ईवीएम पर एकजुट रणनीति के साथ पहले चुनाव आयोग और फिर राष्ट्रपति से मिलने का निर्णय लिया गया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी इस बैठक में मौजूद नहीं थे हालांकि पार्टी सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रपति से विपक्षी दलों की मुलाकात के दौरान राहुल के प्रतिनिधिमंडल में शामिल होने की संभावना है।

राहुल का पीएम पर निशाना,बोले- मोदी की कश्मीर पालिसी फेल

नई दिल्ली

कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कश्मीर पालिसी पूरी तरह से फेल साबित हुई है। इसके साथ ही भाजपा व पीडीपी गठबंधन भी सवालों के घेरे में आ गया है। जम्मू-कश्मीर की जनता ने इसे पूरी तरह से नकार दिया है।

ट्विट के जरिए राहुल गांधी ने कहा कि दशकों तक लगातार मेहनत के बाद जम्मू-कश्मीर के लोगों में लोकतंत्र के प्रति विश्वास बहाल किया गया था लेकिन भाजपा व पीडीपी की गठबंधन सरकार ने महज तीन वर्षों में सब कुछ खत्म कर दिया। लोकसभा उपचुनाव में महज

सात फीसदी मतदान होना इसी बात को दर्शा रहा है। मतदान के दौरान आठ लोगों की हत्या भी राज्य की दयनीय स्थिति को दर्शा रही है।

कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को तत्काल त्यागपत्र दे देना चाहिए। उनका कहना है कि लोकसभा उपचुनाव को पारदर्शी तरीके से कराने के लिटमस टेस्ट में राज्य सरकार फ्लाप साबित हुई है। उनका कहना है कि सात फीसदी मतदान दर्शा रहा है कि लोगों ने गठबंधन सरकार को पूरी तरह से नकार दिया है।